DR. M. M. S. SIDDHU: These examples show what the state of affairs is, because in answers, written answers, to questions, they have denied saying that there is nothing like this. I have before me zerox copies of the case history sheets which, if you like, I shall place on the Table of the Houses . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can pass them on to the Minister.

DR. M. M. S. SIDDHU: Now there was another patient with a congestive heart failure in labour. She was admitted at 10.45 P.M. on 14-4-1982 and the M.S., when called for through "call book", is reported to have written—"Under the circumstances you should not have admitted and transferred her before hospitalization."

Now, is it a hospital where the Medical Superintendent wants an emergency case not to be admitted? There is another case where, when she was asked to come by the duty doctor, it is written that "the ambulance is not available and, therefore, she cannot come." She lives within a distance of fifty yards. After that the patient in the night has to be transferred for caesarian section to another hospital when there is no ambulance available. But as far as she is concerned, she will not come.

When these complaints were made by some Doctors, all the ten or twelve Doctors who have complained were transferred. Is this the way to treat the complaints? And the enquiry says that she must remain, but the ten or twelve Doctors who have comes without number given the complaints were all transferred. Not one or two, but all the twelve of them were transferred.

Not only this. Her behaviour towards nurses is also not good. They have also given complaints copies of which are with me. As far as Class IV *employees are concerned, she has* the habit of boxing their ears. This has been her attitude.

There has been neglect; there has been perfunctory examination of patients; even minimum required investigations are not carried out, there have been failures to visit patients; ambulances are not made available; telephones are not allowed to be used at night.

Under these circumstances, I have raised my feeble voice against malfunctioning of the said maternity hospital only encouraged by the hope that with your kind support an impartial enquiry would be conducted in all *aspects of functioning of the hospital.* The charges are serious and cannot be brushed aside on the plea that it falls in the domain of the municipal corporation.

The Government should not abdicate its authority, responsibility and duty. Therefore, I demand that a complete enquiry be conducted by the Director-General of Health Services or the Additional DGHS personally covering all the aspects of the hospital functioning and a report the submitted to the House with the action taken thereon. Secondly, all those found guilty of neglect of the patient care or dereliction of duties be dealt with according to law. The Government should ensure peaceful, cooperative, team-spirit amongst all persons working in the hospital, Lastly, the hospital must ensure minimum *standard of patient care, commen*surate with the status of 100 bedded hospital. If the Government cannot even guarantee and safeguard this then, may I suggest, in all humility that the Government advise the Corporation to change the name of the hospital to that of "Butchery or Slaughter House"?

REFERENCE TO THE INADEQUATE RAINFALL RESULTING IN DROUGHT CONDITIONS IN SEVERAL DISTRICTS OF MAHARASHTRA

श्री विट्ठल राव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय,

[श्री विट्ठल राव माधवराव जाधव]

मैं, देश में जो सूखा पड़ रहा है और उसके कारण महाराष्ट्र में जो पानी की कमी है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, इस समस्या के बारे में आपके सामने कहना चाहता हूं । मेरे सामने भारत का नक्शा है और इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, अरुणाचल, मेघालय और गुजरात, इसमें आज तक जितनी बारिश होनी चाहिए थी उसमें सिर्फ 20 प्रतिशत बारिश हुई है ।

अब मैं महाराष्ट्र पर आता हूं । जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, आधा हिस्सा महाराष्ट्र का ऐसा है जिसमें बहुत बारिश कम हुई है और वहां क्राप्स का सवाल पैदा नहीं होता । कल ही मुख्य मंत्री ने सब एम० पीज की मीटिंग बुलाई थी । उस मीटिंग में उन्होंने जानकारी दी कि सात जिलों में बहुत बड़ा सूखा पड़ा हुआ है । लेकिन आज हालत यह है कि पहले सात जिले थे लेकिन अब 19 जिलों तक ऐसी हालत हो चुकी है, वहां बारिस नहीं है । इसलिये हालत अब बहुत ही गंभीर बनती जा रही है । महाराष्ट्र में पूना, सावली, सतारा, सोल्हापुर, नासिक, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड़ अप टु नानडाड का हिस्सा, जहां बारिश बहुत कम हुई है वहां हालत यह है कि नगर जिले में 450 टैंकर्स चल रहे हैं । गांव में पानी के लिये जैसी आदमियों के लिये समस्या बहुत कठिन है उससे ज्यादा जानवरों के लिये पानी की समस्या है । वहां जो बड़े बड़े डाम हैं वहां भंडारधारा और कोयला जहां पर बम्बई के लिये इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है उसमें पानी ज्यादा नहीं है । इस लिहाज से हम यह चाहते हैं क पहले आदमी को पानी दिया जाय उसके बाद जानवरों को पानी दिया जाय । जहां तक जानवरों के लिये चारे की हालत है 200 रुपया सी पेंडी का रेट है । ऐसी हालत वहां है । तो मैं यह चाहता हूं कि इस हालत का समाना महाराष्ट्र सरकार बड़ी अच्छी तरह से कर रही है और हमें बड़ी अच्छी तरह से जानकारी दी गई है । दूसरी बात यह है कि जो बम्बई में हड़ताल चल रही है उनमें से दो लाख फेमलीज अभी रूरल एरियाज में चली गई हैं तो उनका जो अडिशनल वर्डन है 6 करोड़ रुपया हर महीने का वह रूरल एरिया पर आता है । यह भी एक संकट है और उसके बाद सूखे का दूसरा संकट है । इसलिए महाराष्ट्र सरकार के सामने डबल संकट खड़ा हो चुका है । इस लिहाज से मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर कुछ फाडर कैम्पस बनाना जरूरी है और जैसे नगर जिले में टैंकर्ज से पानी पिलाया जा रहा है उसी प्रकार महाराष्ट्र में जहां पानी की कमी है उस जगह पर टैंकर्ज से पानी पिलाना बहुत जरूरी है । आप जानते हैं कि गोदावरी नदी साउथ इंडिया में सब से बड़ी नदी है । हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर की नदी है फिर भी नासिक से ले कर औरंगाबाद तक उस नदी में पानी नहीं है इतनी हालत खराब हो चुकी है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे आपने देश में कंस्ट्रक्टिव काम शुरु किये हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन आफ डैम है जिनका पानी फेमिन अफेक्टिड एरियाज में चला जाए वैसे कंस्ट्रक्टिव काम आपको करने चाहियें । उसी तरह से फेमिन अफेक्टिड एरिया पूना डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट है, जिसको 1982 में पूरा होना था उस पर अभी तक काम शुरु नहीं हुआ अगर इसके लिए ज्यादा बजट में धन दिया जाए तो उसका काम पूरा हो

सकता है । उसके बाद (समय की घंटी) अभी एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । उसके बाद जायकवाडी, है, उसके बाद विष्णुपुरी है (समय की घंटी)

श्री उपसभापति : यह तो सब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यहां से क्या होगा । हो गया । (व्यवधान)

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : उनको अगर ज्यादा पैसा मिल जाए । इसी प्रकार से नेशनल हाईवेज है, रोडवेज है, रेलवेज है, रूरल इंडस्ट्रीज है, एग्रो-इंडस्ट्रीज हैं, ग्रामोध्योग है, इम्पलायमेंट गारंटी स्कीम है, इन सब लोगों द्वारा अच्छी तरह से तेजी से काम किया जाए जिससे पानी की समस्या हल हो जाए तो महाराष्ट्र को सुविधा हो सकती है ।

Reference to the Alleged atrocities on the Scheduled Caste people in Bhasahpur, Rajasthan

श्री हरी शंकर भाभडा (राजस्थान) : मैं सरकार का ध्यान राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों पर पिछली 9 अगस्त को बड़ा अत्याचार हुआ, 10 हजार आदमियों की भीड़ ने इकट्ठे हो कर बीस मकान जला दिये, 9 दुकानें जला दी, लाखों रुपये का नुक्सान हुआ, पत्थर चले, गोलियां चलीं, 8 आदमी उस में घायल हुए, प्रशासन सोता रहा इसकी ओर दिलाना चाहता हूं । क्योंकि जिस आदमी ने यह करवाया वह वहां के पुराने राजघराने का कुंवर अरुण सिंह हैं जो अपने आप को कांग्रेस (आई) का सदस्य बताता है । कांग्रेस वाले कहते हैं कि वह नहीं है लेकिन वह कहता है कि मैं हूं । उसने 6 तारीख को अल्टीमेटम दिया था कि 9 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे । 10 हजार आदमी आए और उन्होंने सब काड किया। अब उसने 16 तारीख को फिर प्रदर्शन करने की घोषणा की है । उसका परिणाम यह है कि भरतपुर तहसील के अनेक गांवों में जिनमें कुछ जाटव परिवार हैं वे लोग अपने घरों को छोड़ कर भाग गये हैं । सुनारी, नगलाभगत, हथेनी गांव के अलावा डोग तहसील में भी गांव छोड़ कर जा रहे हैं । इस प्रकार आतंक की अवस्था गांव में अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रही है और यह घोषणाएं कर के की जा रही है और प्रशासन चुप है । यहां तक कि वहां के गृह राज्य मंत्री भी उसी इलाके के धौलपुर के रहने वाले हैं उसके बावजूद भी इस प्रकार के कांड हो रहे हैं इसलिए केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये ।

REFERENCE TO THE NON-SUPPLY OF FOODGRAINS TO THE FAIR PRICE SHOPS IN WEST BENGAL

SHRI ARABINDA GHOSH (West Bengal): Sir, my Special Mention is about the non-supply of ration to the ration shops in West Bengal by the Food Corporation of India causing great hardship to the consumers. In West Bengal there are already 13 districts which are drought-affected and the loss due to the crop failure amounts to about Rs. 100 crores. The details of this have been forwarded by the State Government to the Centre. There is no buffer stock with the FCI in West Bengal The ration shops are going dry. The demand is for 1,75,000 tonnes of rice and 1,35,000 tonnes of wheat. But we have so far received only 1,45,000 tonnes of rice and 60,000 tonnes of wheat for the months of June and July 1982. When we raise the question in the House, the hon. Minister says that the Government is supplying the highest quantities of foodgrains to West Bengal and give some statistics. I quote our statistics from our Government as follows: